

**पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय**

24-फरवरी-2019 18:56 IST

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम-किसान योजना और अन्य पहलों के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

जय जवान जय किसान

जय जवान जय किसान

जय जवान जय किसान

मंच पर उपस्थित सभी महान्भव और यहां गोरखपुर में भारी संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे किसान भाईयो और बहनों.... तकनीक के माध्यम से देश भर से जुड़े किसान भाईयो और बहनों का मैं आपका हृदय से फिर एक बार अभिवादन करता हूं।

आपको ख़शी होगी आज गोरखनाथ के इस कार्यक्रम से, इस स्थान के कार्यक्रम से, गोरखपुर की धरती से, हिन्दुस्तान के दो लाख गांवों के common service centre में सैकड़ों किसान इकट्ठे हुए हैं और इस अवसर के वे भी भागीदार बने हैं।

साथियों, बाबा गोरखनाथ की धरती पर आप सभी के बीच मूझे अनेक बार आने का सौभाग्य मिला है लेकिन आज का दिन देश के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। आज का दिवस सामान्य दिवस नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था। उसी मंत्र को आज इतने सालों के बाद किसान के खेत तक, किसान के घर तक, किसान की जेब तक अगर उतारने का काम हो रहा है तो आज के इस पवित्र दिवस पर हो रहा है।

आजादी के बाद किसानों से जुड़ी ये सबसे बड़ी योजना आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से मेरे देश के करोड़ों-करोड़ों किसान भाईयो बहनों के आशीर्वाद से आरंभ हो रही है। मैं गोरखपुर के लोगों को तो दोहरी बधाई देता हूं क्योंकि वो **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि** की शुरुआत के साक्षात् गवाह बन रहे हैं।

भाईयो और बहनों, आज ही गोरखपुर और पूर्वांचल के विकास से जुड़ी लगभग 10 हजार करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। 10 हजार करोड़ रुपया.... स्वास्थ्य, सड़क, रेल, रोजगार, गैस जैसे क्षेत्रों से जुड़ी ये तमाम परियोजनाएं इस क्षेत्र के जीवन को आसान बनाने वाली हैं। इसके लिए गोरखपुर सहित पूर्वांचल को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

भाईयो और बहनों, **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि** के शुभारंभ के अवसर पर मैं देश भर के करोड़ों किसान परिवार को भी बहत-बहत बधाई देता हूं। इसके अलावा करोड़ों पशुपालकों दूध के व्यवसाय से जुड़े किसान परिवारों और मतस्य पालन... मछली पालन और उसके व्यवसाय से जुड़े बहन भाईयों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

साथियों, किसानों के लिए पहले की सरकारों ने बातें तो बहत की, कागज पर योजनाएं भी बनाईं लेकिन उनकी मंशा किसान को सशक्त करने की नहीं बल्कि किसान को छोटी-छोटी चीज के लिए लगातार तरसाने की थी उनमें किसान का भला करने की नियत नहीं थी इसलिए वो किसानों के लिए कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते थे।

भाईयो और बहनों इसी स्थिति को बदलने के लिए आपने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनाने का अवसर दिया। हमने किसान की छोटी-छोटी दिक्कतों पर ध्यान देने के साथ ही उनकी चूनातियों के सम्पूर्ण निवारण पर भी काम किया है। किसान परी तरह से सशक्त और सक्षम बनें इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। हमारी सरकार बहत ईमानदारी से कोशिश कर रही है कि देश के किसानों को हर वो साधन, संसाधन दिए जाए जिससे वो वर्ष 2022 तक अपनी आय दोगुनी कर सके।

साथियों, बीते साढ़े चार वर्षों के अपने प्रयासों को और मजबूती की इस कड़ी में किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हं। अब से कुछ मिनट पहले देश के एक करोड़ एक लाख किसानों के खातों में इस योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का सौभाग्य मुझे मिला जिसको आपने तालियों के बाजे-गाजे के साथ उसका स्वागत किया है।

मुझे बताया गया है कि देश के 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के किसान इसमें शामिल हैं। इन किसानों को 2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकि किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के 2000 रुपए अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब-करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में दो-दो हजार की पहली किस्त जमा होगी।

भाईयो और बहनों और मैं आपको ये बता दूं ये तो अभी शुरुआत है, इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75 हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। देश के वो 12 करोड़ छोटे किसान जिसके पास 5 एकड़ या उससे कम भूमि है ऐसे सभी किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। अब किसानों को बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना होगा।

केंद्र सरकार हर साल जो छः हजार रुपये सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी उससे जरूरत के सारे काम कर सकते हैं। इसी काम के लिए दो हजार रुपये की पहली किस्त आज अनेक किसानों के खाते में जमा की गई है। इनमें से कुछ किसानों को थोड़ी देर पहले Certificate भी दिए गए हैं। मैं फिर कहंगा जिन किसानों को आज पहली किस्त नहीं मिली है उन्हें आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में पहली किस्त की राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी।

भाईयो और बहनों, **पीएम किसान सम्मान निधि** के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे उसकी पाई-पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। राज्य सरकारों को कुछ नहीं करना है। बस ईमानदारी से अपने-अपने राज्य के किसानों की सही सूची बनाना है। और वो लिस्ट तुरंत हमको पहुंचाना है। अगर जितनी जल्दी सूची आ जाएगी और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, बिहार सरकार का, गुजरात सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, उत्तराखंड की सरकार का ऐसी कई सरकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूं... कि उन्होंने इस काम को प्राथमिकता दी लेकिन ऐसी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जिनकी नींद अभी खुली नहीं है... उनको लगता है कि इस पर वो राजनीति करने जाएंगे।

मैं इन सरकारों को चेतावनी देता हूं अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इस लाभ से वंचित रह गए तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्आयें आपकी राजनीति को तहस-नहस कर देंगी। अरे.... आप विरोधी दल की सरकार हो सकती हो लेकिन मेहरबानी करके किसान तो हमारे देश का है उसके साथ राजनीति क्यों करते हो, क्यों उसके साथ खिलवाड़ करते हो।

भाईयो और बहनों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इस योजना को लेकर किसी के बहकावे में न आएं। हमारे विरोधियों ने, महामिलावटी लोगों ने, ये योजना का सुना तो आपने पार्लियामेंट में देखा होगा..... चेहरा लटक गया था, मरे पड़े थे... मरे पड़े थे, उनको लग रहा था सारे किसान मोदी-मोदी करने लग गए हैं। और इसलिए अब क्या कर रहे हैं अब झूठ बोलना, अफवाह फैलाना... ये तो मुझे लगता है शायद उनका जन्मजात स्वभाव है.... जन्मजात स्वभाव है। इसलिए अब नई अफवाह चालू की है उन्होंने अफवाह ऐसी चालू की है और किसान इसको समझे..... उन्होंने अफवाह ऐसी चालू की है कि मोदी ने अभी दो हजार रुपया दिया है बाद में भी दो हजार देगा उसके बाद भी दो हजार देगा लेकिन साल भर के बाद ये मोदी वापिस ले लेगा..... वापिस ले लेगा.....

मेरे किसान भाईयो और बहनों ये जो पैसा दिया जा रहा है... ये आपके हक का है, कोई इसको वापिस नहीं ले सकता है न मोदी वापिस ले सकता है न राज्य की कोई सरकार भी वापिस ले सकती है। और इसलिए ऐसी अफवाह फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे देना.... भाईयो और बहनों।

मेरे किसान भाईयो और बहनों जब केंद्र में किसान का हित सोचने वाली, किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है तभी इस तरह की योजनाएं मूमकिन होती हैं। जमीन पर उतरती है। नामूमकिन को भी मूमकिन करके दिखाती है। अब पहले की सरकारों की अब ये जरा समझने जैसा विषय है भाईयो और आप गांव-गांव बताएंगे.... जो बात मैं समझा रहा हूं वो गांव-गांव बताओगे, हर किसान को बताओगे, सच्चाई उनको समझाओगे, झूठ फैलाने वालों को करारा जवाब दोगे, पक्का दोगे मैं आपको समझाता हूं ये कांग्रेस वाले चुनाव के पहले, ये सारे महामिलावटी लोग ऐसे ही हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो इनके सारे चेले-चपाटे हों, वो क्या करते हैं दस साल में एक बार उनको किसान याद आता है..... दस साल में एक बार और वो भी चुनाव के पहले याद आता है और फिर कर्जमाफी का बखार उनको चढ़ने लग जाता है..... कर्जमाफी का बखार उनको चढ़ने लग जाता है..... और कर्जमाफी का बखार चढ़के रेवड़ी बांट करके, किसान की आंख में धूल झाँक करके वोट बटोर लेना ये चालाकी वो सीख गए थे लेकिन उनको पता नहीं था अब उनको मोदी मिला है मंहगा

पड़ जाएगा। उनकी पोल खोलकर रख देगा। उनके झूठ के नकाब को खोल करके रख देगा। और सच्चे किसान की सेवा क्या होती है ये मोदी करके दिखाएगा और इसलिए पार्लियामेंट में देखा होगा उनके चेहरे लटके हुए थे। और हमने सिर्फ चुनावी वादा करने के लिए घोषणा नहीं की। हम पार्लियामेंट में बोले हैं और बजट में पैसों का प्रावधान करके बोले हैं। ये हमारी ईमानदारी है।

आप याद करिए साल 2008 में छः लाख करोड़ रुपये का कर्ज किसानों पर था। जरा मेरे साथ बोलिए मैं बताता हं 2008 में सरकारी दफ्तर के हिसाब से, बैंकों के दफ्तर के हिसाब से.... किसानों का पूरे देश का कर्ज था... छः लाख करोड़ रुपया कितना..... कितना.... छः लाख करोड़ रुपया, अब उन्होंने कर्जमाफी चुनाव के पहले घोषणा की तो ये छः लाख करोड़ रुपया माफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था.... आप जरा जोर से बोलिए होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था.... ये छः लाख करोड़ रुपया किसानों का माफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था.... 2009 में चुनाव हुआ... फिर से वो कर्सी से चिपक गए, फिर रिमोट कंट्रोल चालू हो गया... और क्या हुआ मालूम है आपको, क्या हुआ मालूम है देश को किसी को मालूम नहीं है, सब अंधेरे में हैं और इनके चेले चपाटे भी चूष.... छः लाख करोड़ का कर्ज था माफ कितना किया सिर्फ.....सिर्फ.....सिर्फ... आंकड़ा याद रखिए छः लाख करोड़ के सामने मात्र 52 हजार करोड़ रुपया माफ किया। कितना माफ किया.... कितना माफ किया... कितना माफ किया..... कितना करने की जरूरत थी.... आप मूझे बताइए ऐसी झूठी बातों करने वालों पर देश का किसान भरोसा करेगा क्या... ऐसा झूठ करने वालों को सजा करेगा कि नहीं करेगा और भाईयो और बहनों ये 52 हजार करोड़ रुपया भी दस साल में एक बार और वो भी चुनाव के पहले बड़ी-बड़ी बातें अब ये उन्होंने जो लिस्ट बनाई वो भी किसकी जो उनके सिपहसालार थे उनकी सब किसानों की नहीं..... 12-13 करोड़ किसान उसमें से सिर्फ 2 या 3 करोड़ किसानों को ही सिर्फ ये 52 हजार करोड़ रुपया बांट दिए गए। उसमें भी 35 लाख तो ऐसे निकले जिनका कोई किसानी से लेना देना ही नहीं था.....बताइए भाई.....इतना बड़ा घपला... क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या..... ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या।

भाईयो और बहनों दस साल में 52 हजार.... हम जो योजना लाए हैं। वो हर साल.... हर साल ये एक समय के लिए नहीं है... हर साल... साल में तीन बार और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75 हजार करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा होगा। उन्होंने दस साल में 52 हजार करोड़ दिया था। हम दस साल में साढ़े सात लाख करोड़ रुपया देगे... कितना.... साढ़े सात लाख करोड़ रुपया.... कितना... साढ़े सात लाख करोड़... कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई मेरा-तेरा नहीं, न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर हर किसी को 5 एकड़ और उससे कम जमीन है उन सबके खाते में सीधा पैसा जाएगा।

भाईयो बहनों, इनकी योजना... ये दस साल में एक बार वोट बटोरने की, किसान की आंख में धूल झाँकने की योजना थी उसमें गांव में अगर सौ किसान है... तो कहीं पर 20 को लाभ मिला, किसी को 22को मिला, कहीं पर 25 को मिला। हमारी योजना ऐसी है हर वर्ष मिलेगी, देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगी और गांव में अगर सौ का हिसाब लगा लें तो सौ में से नब्बे किसानों को मिलेगी भाईयो बहनों नब्बे किसानों को। सोचिए, किसानों को सीधे पैसा देकर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा निवेश मोदी सरकार कर रही है। इसका आप अंदाज लगा सकते हैं।

साथियों, हमारे लिए यह भी बहुत आसान था कर्जमाफी का फैसला... कोई मुश्किल काम नहीं था। हम भी रेवड़ी बांट देते, हम भी चुनाव में अपना खेल खेल लेते... लेकिन मोदी ऐसा पाप कभी करता नहीं है। मोदी ऐसा पाप के लिए कभी सोचता नहीं है।

आप सोचिए हमारी सरकार **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** पर ही करीब-करीब एक लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है। इतनी बड़ी राशि हम लगा रहे हैं। ताकि देश में जो सिंचाई परियोजनाएं तीस-तीस, चालीस-चालीस साल से अधूरी थी, लटकी हुई थी, उन्हें पूरा किया जा सके।

हमने देश भर की 99वें ऐसी परियोजनाएं चूनी थी जिसमें से 70 से ज्यादा अब पूरी होने की स्थिति में अब आ चुकी है। इन परियोजनाओं की वजह से किसानों को लाखों हेक्टर जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिल रही है और ये वो काम है जो किसानों की आने वाली कई पीढ़ियों तक को लाभ देने वाला है।

साथियों, इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था, कोई दबाव नहीं था। सिंचाई परियोजनाओं को पूरा न करके कर्जमाफी करना बहुत आसान रास्ता था। लेकिन सच्चाई ये है कि कर्जमाफी से सिर्फ ऊपरी स्तर के कुछ किसानों को फायदा होता, कांग्रेस के चेले चपाटों का लाभ होता, मेरे गरीब किसान का लाभ नहीं होता। वो भी ऐसे किसान जिन्होंने किसी न किसी बैंक से लोन लिया था उनको लाभ मिलेगा, आखिर उन करोड़ों किसान परिवारों के बारे में कौन सोचता जो बैंक के बजाए किसी दूसरे से कर्ज लेते हैं और हमारे देश में इनकी संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है।

मेरा किसान भाईयो और बहनों ये नया भारत है इसमें केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए भेजती है वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। अब वो दिन चले गए जब केंद्र सरकार से एक रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसे मिलते थे... बीच में कोई पंजा 85 पैसे मार लेता था और सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था, 15 पैसा...

पीएम किसान सम्मान निधि को भी फूल प्रफ बनाया गया है ताकि आप किसान भाईयो बहनों का अधिकार कोई छीन न सके। इस योजना में किसी भी प्रकार के बिचौलिए के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसका पंजीकरण नंबर आपके लिए काफी होगा। वैसे तो जनधन बैंक खाते सभी के लिए खुल गए हैं लेकिन हां अगर अभी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे। मैं किसी बिचौलिए के हाथ में एक नया पैसा जाने नहीं दूंगा।

साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची... ये भी जरा आप बराबर गांव को समझाना भाईया ये ईमानदारी का रास्ता यही है। साथियों तमाम लाभार्थियों की सूची पहले ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की जाएगी और फिर इसको ऑन लाइन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पूरी ट्रांसपैरेंसी... अगर आपको लगता है कि आप इस योजना के लाभार्थी हैं लेकिन सूची में आपका नाम नहीं है तो अपने ब्लॉक में, या फिर जिला प्रशासन से आप संपर्क कर सकते हैं।

भाईयो बहनों हमारी सरकार एक नई अप्रोच के साथ बीज से बाजार तक, खेत से खलिहान तक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है। जो बाते लोग पहले नामुमकिन समझते थे उन्हें मुमकिन कर रही है। पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार द्वारा दो चरणों में 17 करोड़ से ज्यादा soil health card दिए जा चुके हैं। यूरिया की शत-प्रतिशत नीमकोटिंग का फैसला लेकर हमने खाद का दुरुपयोग.. खाद की चोरी रोका है। अच्छे बीज के लिए हमने रिसर्च को बढ़ावा दिया है।

साथियों, खेती पर होने वाला खर्च कम करने की कोशिश के साथ-साथ किसान को पैदावार की उचित कीमत मिले इसके लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। ये हमारी सरकार ही है जिसने एमएसपी पर किसानों की बरसों पुरानी मांग को भी पूरा किया है। रबी और खरीफ की 22 फसलों का समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना से भी अधिक तय किया गया है।

और भाईयो बहनों आज जो किसान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं... 2007 से एक एमएसपी की फाइल उनके पास पड़ी थी, फाइल दबा करके बैठ गए, अगर 2007 में आपने निर्णय कर लिया होता.... मेरा देश का किसान कभी कर्जदार नहीं हुआ होता... ये आपका पाप है.... ये आपकी बेईमानी है, जिसने मेरे देश के किसान को तबाह किया है।

भाईयो और बहनों, मौसम की मार से किसानों को बचाने के लिए **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** भी बनाई गई है। भाईयो और बहनों किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले और उसकी लागत कम हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इनाम प्लेटफार्म से देश भर की सैंकड़ों मंडियों को जोड़ने का काम चल रहा है। इससे किसानों को सीधे देश भर की किसी भी मंडी में ऑनलाइन अपनी उपज बेचने का विकल्प मिलेगा। इससे कोई बिचौलिया कीमतों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगले एक दो वर्षों में इस माध्यम का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है।

साथियों, किसान अपनी आय दोगुनी कर सके, इसके लिए सरकार खेती के पारंपारिक तौर तरीकों के अलावा अन्य विकल्पों को भी बढ़ावा दे रही है। जैसे मधुमक्खी पालन, organic farming, रेशम का उत्पादन sola farming ऐसे अनेक नए क्षेत्रों में हम किसान को आगे ले जा रहे हैं। इसके अलावा पशुपालन और मछली पालन के लिए तो हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं।

भाईयो और बहनों खेती हो या दूसरे व्यवसाय इन सभी को विस्तार देने के लिए बैंको से ऋण की सुविधा को भी बहत आसान बनाया गया है। इसी का परिणाम है कि पिछले वर्ष 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कृषि लोन किसानों को दिया गया है।

साथियों, किसान भाईयो और बहनों को कर्ज मिलने में आसानी रहे इसके लिए हमने एक और बड़ा फैसला लिया है, बहत बड़ा फैसला लिया है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सिर्फ 1 लाख रुपये तक का ऋण बिना गारंटी लिया जा सकता था, अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। अब मेरे किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सिर्फ 1 लाख नहीं.... 1 लाख 60 हजार रुपये तक का कर्ज बिना गारंटी ले पाएंगे।

आज से ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा हमारे दूध उत्पादकों और मतस्य पालकों के लिए भी शुरू की गई है। जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है उनको अलग से पशु पालन और मछली पालन के लिए दो लाख रुपये तक की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे इन दोनों क्षेत्रों में फंड की उपलब्धता बढ़ जाएगी और हमारे पशुपालकों और मछुवारे भाई बहनों को दूसरे लोगों से कर्ज लेने पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मछली पालन से जुड़े हर पहलू पर ध्यान देने के लिए इस बजट में सरकार ने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाने का भी ऐलान किया है।

आपको मालूम हुआ देश आजाद हुआ लेकिन आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय नहीं था। ये अटल बिहारी वाजपेयी... उन्होंने... आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया था। देश आजाद होने के बाद north east के विकास के लिए कोई मंत्रालय नहीं था। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने north east के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया था। और अब फिर एक बार भाजपा की सरकार आई है कि देश में समुद्री तट पर, नदी के तट पर हमारे जो माछीमार भाई बहन रहते हैं उनके विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए माछीमार के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाने का हमने फैसला किया है। ताकि उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए।

साथियों, इसके साथ ही एक व्यवस्था ये भी की गई है कि अब प्राकृतिक आपदा से प्रवाह होने की स्थिति में किसानों को कृषि ऋण में छूट की सीमा एक वर्ष से बढ़ाकर तीन से पांच वर्ष तक कर दी गई है। अब इसके कारण प्राकृतिक आपदा के बाद किसान को किसी से कर्ज लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, उसको समय मिलेगा अगर किसान इस अवधि में समय पर अपने कर्ज के भुगतान करते हैं तो उन्हें..... ये भी सुनिए... अगर वो कर्ज में भुगतान करते हैं तो उन्हें ब्याज दर में तीन प्रतिशत अतिरिक्त छूट का भी लाभ मिलेगा।

भाईयो और बहनों, गोरखपुर और पूर्वांचल के पशुपालकों, दूध उत्पादकों के लिए तो आज डबल खुशी का दिन है क्योंकि आज ही 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाली नई डेयरी का लोकार्पण किया गया है। इससे लगभग 50 हजार दूध उत्पादक इससे सीधे लाभान्वित होंगे और साथ में रोजगार के हजारों अवसर भी बनेंगे।

भाईयो और बहनों, पशुपालकों के लिए एक और अच्छी खबर है, साथियों.. हमारी सरकार ने पहली बार देसी गाय और भैंसों को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष **राष्ट्रीय गोकुल मिशन** आरंभ किया था। इस वर्ष इसको विस्तार देते हुए **राष्ट्रीय कामधेनु आयोग**, ये बनाने का फैसला लिया गया है। ये आयोग पशुधन से जुड़े कानून है, जो नीतियां हैं उनकी समीक्षा करेगा और दूध का अधिक उत्पादन कैसे हो इसके लिए उपाय सझाएगा। इस आयोग का एक अहम कार्य गऊमाता के कल्याण, देश भर में मौजूदा गौशाला हों और गऊसदन हो इनसे जुड़ी जानकारी जुटाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी रहेगा।

साथियों, इस प्रकार एक बड़ी योजना.... ये योजना भी मेरे किसान भाईयो बहनों, देश भर के किसान भाईयो बहनों एक और योजना की बात मैं बताने जा रहा हूं ये भी आपको कितना बड़ा काम करने वाली है। इसका अंदाज लगाइए... हमने एक नई योजना लाए हैं। **किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान** और हमने इसी हफ्ते इसकी मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसानों को 17 लाख से अधिक सोलर पंप सूर्य की गर्मी से चलने वाले पंप की मदद मिलेगी। जो उनको सिंचाई पर होने वाले, बिजली का खर्च हो, डीजल का खर्च हो इससे उनको मुक्ति मिल जाएगी।

इसके अलावा दस लाख सोलर पंपों को बिजली ग्रिड से जोड़ने में किसानों की मदद की जाएगी जिससे वो सिंचाई तो वो मुफ्त में कर ही पाएंगे लेकिन सोलर से अगर ज्यादा बिजली पैदा हुई, जरूरत से ज्यादा बिजली है तो ये बिजली भी सरकारों को बेच करके, बिजली बेच करके भी कमाई करेगा मेरा किसान.... इसी प्रकार किसानों की बंजर जमीन पर पांच सौ किलो वॉट से दो मेगा वॉट तक के सोलर प्लांट लगाने की भी योजना है। ये अन्न दाता को ऊर्जा दाता बनाने के हमारे व्यापक अभियान का हिस्सा है। अब मेरा किसान अन्न दाता तो है, अब वो देश का ऊर्जा दाता भी बनने वाला है।

साथियो, हमारी सरकार आदिवासियों भाई बहनों की आय बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है, हमारे आदिवासी किसानों का भी भला हो, वनधन योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंगल से जो उपज ली जाती है उसकी बेहतर कीमत किसानों को मिल पाए इसके वनधन केंद्र बनाए जा रहे हैं। वन उपज पर जो समर्थन मूल्य सरकार देती है उसमें बीते साढ़े चार वर्ष में तीन बार बढ़ोतरी की गई है। दिसंबर में ही 23 उपजों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं इस दौरान सरकार द्वारा एमएसपी के दायरे में आने वाली फसलों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। चार साढ़े चार वर्ष पहले जंगल से मिलने वाली दस उपजों पर एमएसपी मिलता था अब वो संख्या बढ़ाकर आदिवासी किसानों के लिए ये संख्या बढ़ा करके करीब-करीब 50 कर दी गई है।

मेरे प्यारे भाईयो और बहनों सरकार ने खास करके जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए बांस से जुड़े कानून में भी बड़ा बदलाव किया है। अब आप अपने खेत में भी बांस उगा सकते हैं और उसको बेचकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था। क्योंकि बांस को पेड़ की श्रेणी में रखा गया था। सिर्फ बांस की खेती कर पाएं इतना ही काम नहीं किया इसको व्यापक बाजार मिले इसके लिए भी काम किया जा रहा है।

साथियों, खेती के साथ-साथ गांव और किसान की हर आवश्यकताओं पर भी सरकार ध्यान दे रही है। यहां गोरखपुर में खाद कारखाने पर तेजी से काम चल रहा है। ये कारखाना एक बार फिर इस शहर की पहचान बनने वाला है। इससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध तो होगा ही, किसानों की लागत भी कम होगी।

भाईयो और बहनों, पूर्वांचल में जहां आज ये सभा हो रही है। ये पूरा क्षेत्र परिवर्तन के अभूतपूर्व दौर से गुजर रहा है। उद्योग धंधे हो, connectivity हो, या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं बदलाव स्पष्ट अनुभव हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई है। हाल में एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक एनसेफलाइटिस के कारण इस बार पिछले साल की अपेक्षा अनेक बच्चों का जीवन बचाने में सफलता मिली है।

साथियों, पूर्वांचल की स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती देने के लिए आज अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में 200 बिस्तर वाले super specialty अस्पताल का लोकार्पण आज किया गया है। गोरखपुर एम्स का ओपीडी भवन भी अब सेवा के लिए समर्पित है। आज से यहां मरीजों की जांच और इलाज शुरू हो जाएगा।

साथियों, पूर्वांचल... पूर्वी भारत में सुविधाओं, उद्यमों और रोजगार का एक बहुत बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। इसी को देखते हुए यहां की connectivity को और भी आधुनिक बनाया जा रहा है। गोरखपुर कैंट, कप्तान गंज, बाल्मीकी नगर सेक्शन का बिजलीकरण हो गया है। इसलिए अब इस सेक्शन में बिजली से ट्रेन चल पाएगी जिससे समय की बचत भी होगी और प्रदूषण भी कम आएगी। ऐसी स्थिति में जब भारतीय रेलवे अब पूरी तरह से बिजलीकरण की तरफ बढ़ रही है तब यहां जो electric loco shed है इससे वाराणसी के साथ-साथ यहां भी इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जा सकेंगे। इससे यहां सीधे रोजगार तो उपलब्ध तो होंगे ही, आसपास अनेक प्रकार के सहायक उद्योग भी लगेंगे।

साथियों, हमारी सरकार का प्रयास गोरखपुर समेत पूर्वांचल में स्वच्छ ईंधन और गैस आधारित अर्थव्यवस्था को भी विकसित करने का है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना से पहले ही यहां के खाद कारखानों और घरों में पाइप वाली गैस जैसी परियोजनाओं को लाभ हो रहा है। आज 9 हजार करोड़ रुपये की एक और गैस परियोजना का शिलान्यास किया गया है।

भाईयो और बहनों ये तमाम योजनाएं और परियोजनाएं सबका साथ सबका विकास इसका जीता-जागता उदाहरण है। बीते साढ़े चार वर्षों में केंद्र सरकार ने इस मूल मंत्र पर चलते हुए देश में जनकल्याण और विकास की एक नई धारा का प्रवाह किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, आयुष्मान योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं के लाभार्थियों के चयन बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किए जा रहे हैं।

कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो उसको हमारी सरकार की योजनाओं से लाभ मिलना तय है। किसी के कहने पर नाम चढ़ाने या हटवाने के कारनामों अब बंद हो चुके हैं। ऊपर से जनधन, आधार और मोबाइल जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं से बिचौलियों और फर्जीवाड़ा करने वाले सिस्टम से हटाये जा रहे हैं। यही कारण है कि आज देश, दुनिया के तमाम सर्वे बता रहे हैं कि भारत तेजी से भीषण गरीबी की स्थिति से बाहर निकलता चला जा रहा है।

साथियों, ये सब कुछ किसलिए हो पा रहा है.... ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है... क्यों हो रहा है साहब ये सब... ये क्यों हो रहा है.... इतने सारे काम क्यों हो रहे हैं अभी ... क्या कारण है.... ... क्या कारण है.... ... क्या कारण है.... अरे मोदी कारण नहीं है, कारण तो मेरे आप भाई बहन हैं जिन्होंने 2014 में.... आप मेरे देशवासी हैं, आप मेरे उत्तरप्रदेश के भाई बहन हैं जिन्होंने 2014 में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया था इसके लिए सब हो सका है। गरीब के हित में हमारी सरकार बड़े-बड़े लोगों से, बड़े-बड़े भ्रष्टाचारियों से इसलिए पीट पा रही है क्योंकि आपने उसे बहमत दिया और ऐसे फैसले लेने की आपने मूझे ताकत दी है। ये ताकत ऐसे ही बनी रहे, आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे इसी कामना के साथ मेरे देश के सभी किसान भाई बहनों को आज के इस महत्वपूर्ण योजना के द्वारा लोकार्पण के समय सर झुका करके नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और किसान सम्मान निधि का फायदा सभी 12 करोड़ किसानों को जल्द से जल्द मिले, हर वर्ष मिले.... इस कामना के साथ मैं फिर एक बार आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके जोर से बोलिए

भारत माता की जय

भारत माता की जय

भारत माता की जय

बहुत-बहुत धन्यवाद।

अतुल कुमार तिवारी/शाहबाज हसीबी/ममता

प्रधानमंत्री कार्यालय

अटल जल योजना के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 25 DEC 2019 1:49PM by PIB Delhi

मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री राजनाथ सिंह जी, श्री गजेंद्र शेखावत जी, अन्य महानुभाव और यहां उपस्थित देवियों और सज्जनों !

देशभर के अनेक कॉमन सर्विस सेंटरों से आए हज़ारों लोग, विशेषकर गांवों के पंच-सरपंच भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मनाली से वहां के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, वन मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, सांसद राम स्वरूप शर्मा जी भी तकनीक के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं।

उनके साथ अटल जी के प्रिय गांव से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं।

मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।

आज इस मंच से सबसे पहले मैं देश के लोगों को, दुनिया को, क्रिसमस की बहुत-बहुत बधाई-शुभकामनाएं देता हूं।

Merry Christmas!!!

आज भारत के दो-दो रत्नों, हम सभी के श्रद्धेय अटल जी और महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिवस भी है।

मैं उन्हें नमन करता हूं, देश की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मुझे बताया गया है कि प्रीणी में आज अटल जी की स्मृति में हवन हुआ है, कुछ अन्य कार्यक्रम भी हुए हैं।

साथियों,

आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ी परियोजना का नाम अटल जी को समर्पित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश को लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली, रोहतांग टनल, अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी।

हिमाचल के लोगों को, प्रीणी के लोगों को ये सरकार की तरफ से अटल जी के जन्मदिन पर एक छोटा सा उपहार है।

ये अटल जी ही थे, जिन्होंने इस टनल के महत्व को समझा और इसके निर्माण का मार्ग बनाया था।

अटलजी के नाम पर इस टनल का नामकरण होना, हिमाचल के प्रति उनके लगाव और अटल जी के प्रति आप सभी के आदर और असीम प्यार का भी प्रतीक है।

साथियों,

पानी का विषय अटल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उनके हृदय के बहुत करीब था।

पानी को लेकर उनका विजन, हमें आज भी प्रेरणा देता है।

अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से जुड़ी गाइडलाइंस, ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम हैं।

साथियों,

ये पानी ही तो है जो घर, खेत और उद्योग, सबको प्रभावित करता है।

और हमारे यहां पानी के स्रोतों की क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है।

पानी का ये संकट एक परिवार के रूप में, एक नागरिक के रूप में हमारे लिए चिंताजनक तो है ही, एक देश के रूप में भी ये विकास को प्रभावित करता है।

न्यू इंडिया को हमें जल संकट की हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना है।

इसके लिए हम पाँच स्तर पर एक साथ काम कर रहे हैं।

पहला- पानी से जुड़े जो डिपार्टमेंट हैं, हमने उनके Silos को तोड़ा।

दूसरा- भारत जैसे विविधता भरे देश में हमने हर क्षेत्र की जमीनी स्थिति को देखते हुए योजनाओं का स्वरूप तय करने पर जोर दिया।

तीसरा- जो पानी उपलब्ध होता है, उसके सही संचयन और वितरण पर ध्यान दिया।

चौथा- पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल हो, पानी की recycling हो, इसे योजनाओं में प्राथमिकता दी और

पाँचवाँ- सबसे महत्वपूर्ण- जागरूकता और जनभागीदारी।

साथियों,

चुनाव से पहले जब हमने पानी के लिए समर्पित एक जलशक्ति मंत्रालय की बात की थी, तो कुछ लोगों को लगा कि ये कैसा वादा है।

लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बात पर गौर किया कि क्यों इसकी जरूरत थी।

साथियों,

वर्षों से हमारे यहां पानी से जुड़े विषय, चाहे Resources हों, Conservation हो, Management हो, तमाम ऑपरेशन और काम अलग-अलग डिपार्टमेंट और मंत्रालयों में रहे।

यानि एक तरह से कहें तो जिस Silos की मैं बात करता हूँ, उसका ये बेहतरीन उदाहरण था।

इस वजह से कहीं राज्य और केंद्र सरकार में, कहीं केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों में, कहीं अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था, कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती थीं।

इसका नुकसान ये हुआ कि पानी जैसी मूल आवश्यकता के लिए जो Holistic Approach होनी चाहिए थे, वो पहले की सरकारों के समय अपनाई नहीं जा सकी।

जल शक्ति मंत्रालय ने इस Compartmentalized Approach से पानी को बाहर निकाला और Comprehensive Approach को बल दिया।

इसी मानसून में हमने देखा है कि समाज की तरफ से, जलशक्ति मंत्रालय की तरफ से Water Conservation के लिए कैसे व्यापक प्रयास हुए हैं।

साथियों,

जिस क्षेत्रीय विविधता की बात मैंने की, वो पानी से जुड़ी योजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारे यहां तो कहा जाता है कि हर कोस पर पानी बदल जाता है।

अब जो देश इतना विविध हो, इतना विस्तृत हो, वहां पानी जैसे विषय के लिए हमें हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए आगे बढ़ना होगा।

इसी सोच ने अटल जल योजना का आधार तय किया है।

यानि एक तरफ जल जीवन मिशन है, जो हर घर तक पाइप से जल पहुंचाने का काम करेगा और दूसरी तरफ अटल जल योजना है, जो उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी जहां ग्राउंडवॉटर बहुत नीचे है।

इस योजना से महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, एमपी और गुजरात, इन सात राज्यों के भूजल को ऊपर उठाने में बहुत मदद मिलेगी।

इन सात राज्यों के 78 जिलों में, 8,300 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में भूजल का स्तर चिंताजनक स्थिति में है।

इसका क्या खामियाजा वहां के लोगों को उठाना पड़ता है, वो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए साथी बहुत अच्छी तरह जानते हैं।

इन क्षेत्रों के किसानों की, पशुपालकों की, छोटे-छोटे उद्यमियों की, वहां की महिलाओं की दिक्कतें किसी से छिपी नहीं हैं।

साथियों,

लोगों को इन दिक्कतों से मुक्ति मिले, जल स्तर में सुधार हो, इसके लिए हमें जागरूकता अभियान चलाने होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जरूरी डेटा को जोड़ना पड़ेगा।

और सबसे प्रमुख बात, हमें जल संरक्षण और संवर्धन पर बल देना होगा ताकि पानी की एक-एक बूंद का उचित उपयोग हो।

आखिर ये होगा कैसे?

इस टीम का नेतृत्व कौन करेगा?

अफसर, कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट?

नहीं।

इसके लिए हमें उन लोगों तक जाना होगा, उन लोगों को जोड़ना होगा, जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी के संकट से प्रभावित हैं।

इसके लिए हमें अपनी उन माताओं-बहनों के पास जाना होगा जो घरों की असली मुखिया होती हैं। घरों में पानी का उपयोग जरूरत के अनुसार ही हो, जहां तक संभव हो Recycle किए पानी से काम चलाया जाए, ये अनुशासन घरों के भीतर लाना ही होगा।

इसके लिए हमें किसानों के पास भी जाना होगा।

हमारी खेती भूजल से सिंचाई पर बहुत अधिक निर्भर है।

लेकिन ये भी सच है कि हमारे सिंचाई के पुराने तौर-तरीकों से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाता है।

इसके अलावा गन्ना हो, धान हो, बहुत सी ऐसी फसलें भी हैं जो बहुत ज्यादा पानी चाहती हैं।

इस प्रकार की फसलें, जहां होती हैं, वहां कई बार ये पाया गया है कि इन जगहों पर भूजल का स्तर तेजी से घटता जा रहा है।

इस स्थिति को बदलने के लिए हमें किसानों को वर्षा जल के संचयन के लिए, वैकल्पिक फसलों के लिए जागरूक करना होगा, ज्यादा से ज्यादा माइक्रो-इरिगेशन की तरफ बढ़ना होगा, हमें Per Drop More Crop को बढ़ावा देना होगा।

साथियों,

जब हम घर के लिए कुछ खर्च करते हैं, तो अपनी आय और बैंक बैलेंस भी देखते हैं, अपना बजट बनाते हैं। ऐसे ही जहां पानी कम है, वहां गांव के लोगों को वॉटर बजट बनाने के लिए, उस आधार पर फसल उगाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना होगा।

और यहां अभी गांवों से जो लोग आए हैं, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अटल जल योजना में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी ही है।

आप जितना अच्छा काम करेंगे, उससे गांव का तो भला होगा ही, ग्राम पंचायतों का भी भला होगा।

अटल जल योजना में इसलिए ये भी प्रावधान किया गया है कि जो ग्राम पंचायतें पानी के लिए बेहतरीन काम करेंगी, उन्हें और ज्यादा राशि दी जाएगी, ताकि वो और अच्छा काम कर सकें।

मेरे सरपंच भाइयों और बहनों,

आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी भागीदारी, देश के हर घर तक जल पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

मैं अटल जल योजना से जुड़े सभी 8,300 सरपंचों से कहना चाहता हूं कि आपकी सफलता न सिर्फ अटल जल योजना को कामयाब बनाएगी बल्कि जल जीवन मिशन को भी मजबूती देगी।

कैसे?

ये आपका जानना भी बहुत जरूरी है।

ये देश के प्रत्येक नागरिक को भी जानना जरूरी है।

साथियों,

आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज देश के 3 करोड़ घरों में ही नल से जल पहुंचता है।

सोचिए,

18 करोड़ ग्रामीण घरों में से सिर्फ 3 करोड़ घरों में।

70 साल में इतना ही हो पाया था।

अब हमें अगले पाँच साल में 15 करोड़ घरों तक पीने का साफ पानी, पाइप से पहुंचाना है।

इसके लिए अगले पाँच वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही हैं।

निश्चित रूप से ये संकल्प विराट है, लेकिन हमारे पास सफल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हमें सफल होना ही है।

ऐसे में हमारी प्रतिबद्धता जमीन पर, देश के गांव-गांव में दिखनी बहुत आवश्यक है।

आज जो जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, वो इसमें हमारी मदद करने वाली हैं।

साथियों,

जल जीवन मिशन का ये अभियान सिर्फ हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने से नहीं जुड़ा हुआ है।

हमारी मां बहनों को घर से दूर जाकर पानी न लाना पड़े, उनकी गरिमा का सम्मान हो, उनकी जिंदगी आसान बने, इस मिशन का ये भी लक्ष्य है।

आज भी मैं जब किसी बुजुर्ग मां को पानी के लिए भटकते देखता हूं, जब किसी बहन को सिर पर मटके रखकर मीलों पैदल चलते देखता हूं, तो बचपन की बहुत सी यादें ताजा हो जाती हैं।

देशभर की करोड़ों ऐसी बहनों को पानी जुटाने की तकलीफ से भी मुक्ति दिलाने का समय आ गया है।

जैसे हमने हर घर में शौचालय पहुंचाए, उसी तरह हर घर में जल भी पहुंचाएंगे, ये प्रण लेकर हम निकल पड़े हैं।

जब संकल्प ले लिया है, तो इसे भी सिद्ध करके दिखाएंगे।

साथियों,

गांव की भागीदारी और साझेदारी की इस योजना में गांधी जी के ग्राम स्वराज की भी एक झलक है।

पानी से जुड़ी योजनाएं हर गांव के स्तर पर वहां की स्थिति-परिस्थिति के अनुसार बनें, ये जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस बनाते समय ध्यान रखा गया है।

इतना ही नहीं,

ग्राम पंचायत या पंचायत द्वारा बनाई गई पानी समिति ही अपने स्तर पर पानी से जुड़ी योजना बनाएगी, उसे लागू करेगी, उसकी देखरेख करेगी।

और इसलिए,

हमें, पानी की लाइन की प्लानिंग से लेकर उसके प्रबंधन तक से गांव को जोड़ने का काम हमें करना है।

हमें हमेशा याद रखना है कि गांव के मेरे भाई-बहनों के पास, बुजुर्गों के पास पानी के स्रोतों को लेकर, पानी के भंडारण से जुड़ी बातों का खज़ाना है।

हमें गांव के लोगों से बड़ा एक्सपर्ट और कौन मिलेगा?

इसलिए गांव के लोगों के अनुभव का हमें पूरा इस्तेमाल करना है।

साथियों,

हमारी सरकार का प्रयास, जल जीवन मिशन में ज्यादा से ज्यादा गांव के लोगों को अधिकार देने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का है।

इस मिशन के लिए हर गांव में एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी, गांव के स्तर पर ही एक्शन प्लान बनेंगे। मेरा ये आग्रह होगा कि इस कमेटी में कम से कम 50 प्रतिशत गांव की ही बहनें हों, बेटियां हों।

यही नहीं, साफ पानी आ रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए गांव के ही निवासियों, वहां के बेटे-बेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी।

इसी तरह, कौशल विकास योजना के माध्यम से बड़े स्तर पर गांवों के युवाओं को फिटर, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मिस्त्री, ऐसे अनेक कामों की ट्रेनिंग दी जाएगी।

हां, इन सारे प्रयासों के बीच,

कुछ दुर्गम इलाकों में, कुछ सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में, मौसम और भौगोलिक स्थिति की वजह से पाइप लाइन पहुंचाने में कुछ मुश्किल जरूर आएगी।

ऐसी जगहों को क्या छोड़ देंगे?

नहीं।

ऐसे स्थानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

वहां भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उन गांवों के लोगों को शुद्ध पानी मिले।

साथियों,

जल जीवन मिशन के दौरान एक और नई चीज की जा रही है। इस योजना की मॉनीटरिंग के लिए स्पेसटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

हर गांव में पानी का कितना भंडारण हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, पानी की स्थिति के बारे में सारी जानकारी पर निरंतर नजर रखी जाएगी।

साथियों,

जल जीवन मिशन में सरकार ने ये भी प्रावधान किया है कि आपके गांव में योजना पूरी होने पर सरकार पानी समिति के खाते में सीधे पैसे भेजेगी। ताकि पानी से जुड़ी व्यवस्थाओं की देखरेख और संचालन गांव के लोग ही करें।

मेरा एक और आग्रह है कि हर गांव के लोग पानी एक्शन प्लान बनाएं, पानी फंड बनाएं। आपके गांव में पानी से जुड़ी योजनाओं में अनेक योजनाओं के तहत पैसा आता है। विधायक और सांसद की निधि से आता है, केंद्र और राज्य की योजनाओं से आता है।

हमें ये व्यवस्था बनानी होगी कि ये सारा पैसा एक ही जगह पर आए और एक ही तरीके से खर्च हो। इससे टुकड़ों-टुकड़ों में थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाने के बजाय ज्यादा पैसा एक साथ लग पाएगा।

साथियों,

मैं आज इस अवसर पर दुनिया भर में बसे भारतीयों से भी आग्रह करूंगा कि वो इस पावन अभियान में अपना योगदान दें।

मैं आज इस मंच से, गांव में रहने वाले अपने भाई-बहनों से भी अपील करता हूं, कि वो पानी के संरक्षण के लिए, पानी के वितरण की व्यवस्था को संभालने के लिए, पानी की recycling के लिए आगे आए।

आप अपना समय दें, अपना श्रम दें। आप एक कदम चलेंगे तो सरकार 9 कदम चलेगी।

आइए, एकजुट होकर, कदम से कदम मिलाते हुए, देश के सामान्य जन को स्वच्छ पानी के अधिकार से जोड़ने का अपना दायित्व निभाएं।

आपके प्रयास, आपकी सफलता, देश की जल सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

एक बार फिर अटल जल योजना के लिए, जल जीवन मिशन के लिए पूरे देश को शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद!!!

PM Modi's speech at launch of Atal Bhujal Yojana



VRRK/VJ/AK/MAMTA

(रिलीज़ आईडी: 1597574) आगंतुक पटल : 863

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Punjabi